



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

17 आषाढ़ 1942 (श10)  
(सं0 पटना 429) पटना, बुधवार, 8 जुलाई 2020

---

सं० 08/नि0था0-11-02/2019-6288 सा0प्र0  
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

29 जून 2020

श्री संजय कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1104/11 (1341/08), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-अंचलाधिकारी, रहुई (नालन्दा) के विरुद्ध इंदिरा आवास एवं मुख्यमंत्री आवास योजना में गंभीर अनियमितता बरतने एवं उक्त मामले में निगरानी थाना कांड संख्या-030/2008 दिनांक 29.05.2008 दर्ज होने तथा श्री कुमार को नामजद अभियुक्त बनाये जाने संबंधी प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6691 दिनांक 19.06.2008 द्वारा निलंबित किया गया। तदुपरांत श्री कुमार के विरुद्ध प्रपत्र-“क” गठित करते हुए विभागीय पत्रांक 3620 दिनांक 24.04.2009 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

जिसके क्रम में श्री कुमार द्वारा अपना स्पष्टीकरण (दिनांक 07.02.2011) समर्पित किया गया। विभागीय पत्रांक 5771 दिनांक 24.05.2011 द्वारा उक्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, नालन्दा से मंतव्य की मांग की गई। इस बीच श्री कुमार का निलंबन अवधि एक वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या 12715 दिनांक 23.11.2011 द्वारा उनके जीवन निर्वाह भत्ता में 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई। जिला पदाधिकारी, नालन्दा के पत्रांक 784 दिनांक 04.02.2012 द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर मंतव्य प्राप्त हुआ। जिसमें जिलाधिकारी द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण को अमान्य करते हुए लापरवाही एवं पर्यवेक्षण का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध गठित आरोप पत्र उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उक्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4287 दिनांक 21.03.2012 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमण्डल, पटना के पत्रांक 449 दिनांक 07.06.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जिसमें साक्ष्य के अभाव में आरोपों का प्रमाणित नहीं होने का उल्लेख किया गया। तदुपरांत विभागीय पत्रांक 13847 दिनांक 05.10.2012 द्वारा असहमति का बिन्दू गठित करते हुए श्री कुमार से अभ्यावेदन की मांग की गई। जिसके क्रम में श्री कुमार द्वारा अपना अभ्यावेदन दिनांक 19.10.2012 समर्पित किया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध गठित आरोप, जांच प्रतिवेदन एवं प्राप्त अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई एवं श्री कुमार के विरुद्ध मुख्यमंत्री आवास योजना में बैंक खाता खुलवाने में लापरवाही एवं पर्यवेक्षण की कमी का आरोप पाते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 16477 दिनांक 04.12.2012 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गया:-

(क) निन्दन (वर्ष 2007-08)

(ख) असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक।

पुनः संकल्प ज्ञापांक 4052 दिनांक 11.03.2013 द्वारा श्री कुमार के निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा एवं उक्त अवधि पेंशन के प्रयोजनार्थ गणना की जायेगी का निर्णय लिया गया। उक्त दण्डादेश के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक 15.01.2013 समर्पित किया गया, जिसे सम्यक विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7088 दिनांक 03.05.2013 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

उक्त दण्डादेश के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में वाद सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 11369/2014 दायर किया गया। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.01.2019 को आदेश पारित किया गया।

न्यायादेश का मुख्य अंश निम्नवत् है:-

13. In view of such procedural irregularity, the consequential findings of the Disciplinary Authority based on such illegal and unfair procedure is unsustainable. In this connection, this Court would only reiterate the law as laid down by the Apex Court in the case of Punjab National Bank and Others -VersusKunj Behari Misra, (1998) 7 Supreme Court Cases 84. The punishment imposed by the Disciplinary Authority under communication dated 04.12.2012 being outcome of a procedure in violation of Rule 18 of Bihar CCA Rules, 2005 as also the law in this regard in the case of Kunj Behari Misra (supra) is, therefore, quashed.

14. In view of quashing of the order of punishment, the consequential order issued by the Joint Secretary (respondent No 3) reiterating the illegal order of the Disciplinary Authority and without considering the illegal procedure adopted by the Disciplinary Authority and communicating rejection of petitioner's appeal under Letter dated 03.05.2013 bearing Memo No 7088 are also unsustainable and are hereby quashed.

15. The writ petition is allowed.

16. As a result of quashing of the impugned order, the petitioner would be entitled to all consequential benefits.

17 However, this order would not preclude the respondent-authorities from proceeding against the petitioner by following the procedure prescribed under Bihar CCA Rules, and in accordance with law.

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के विरुद्ध एल0पी0ए0 दायर करने के बिन्दु पर परामर्श हेतु संचिका विधि विभाग भेजी गई। जिसमें विधि विभाग द्वारा निम्न परामर्श दिया गया:-

In my opinion, the findings recorded by the Hon'ble High Court cannot be faulted to the extent that the letter no 972 dated 13-02-2012 of the District Magistrate, Nalanda was nowhere discussed by the Inquiry Officer in his inquiry report. If this letter was not part of the departmental proceeding, then the same could not have been based for recording difference. However, the Presenting Officer did bring on record D.D.C. letter no 3234 dated 12-12-2011 and D.M. letter no 784 dated 04-02-2012. If these two documents are substantially same and similar as that of letter no 972 dated 13-02-2012 of the D.M. Nalanda then a point can be raised that no substantial prejudice is caused to the delinquent. However, the grounds of appeal prepared as draft and kept at page-1175-1173/C, does not suggest the same. Under the given facts, there is very little scope of success if the state proposes to go in appeal against the Single Judge order. The penalty imposed is minor in nature and liberty is already given to continue the proceeding afresh against the delinquent, if desired by the state in accordance with law.

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं विधि विभाग द्वारा दिये गये उक्त परामर्श के आलोक में पुरे मामले की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई। सम्यक विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निम्न निर्णय लिया गया :-

1. श्री कुमार को संसूचित दण्डादेश संबंधी विभागीय संकल्प ज्ञापांक 16477 दिनांक 04.12.2012 तथा पुनर्विलोकन अर्जी अस्वीकृति संबंधी विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7088 दिनांक 03.05.2013 को वापस लिया जाता है।

2. श्री कुमार के विरुद्ध Fresh कार्यवाही हेतु अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा।

उक्त निर्णय, श्री कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1104/2011 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी, रहुई (नालन्दा) सम्प्रति अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण, पदाधिकारी, बाढ़ को संसूचित किया जाता है।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
शिवमहादेव प्रसाद,  
सरकार के अवर सचिव

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 429-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>